

NEXT IAS

दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

ब्रिक्स एवं भारत-ईरान संबंध

www.nextias.com

ब्रिक्स एवं भारत-ईरान संबंध

सन्दर्भ

- रूस के कज़ान में आयोजित 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अवसर पर भारत और ईरान ने एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें उनकी साझेदारी की अप्रयुक्त क्षमता पर प्रकाश डाला गया, जो ऐतिहासिक रूप से समृद्ध रही है, लेकिन हाल के वर्षों में इसमें ठहराव आ गया है।

ईरान और ब्रिक्स

- रूस के कज़ान में आयोजित 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ईरान को ब्रिक्स समूह में शामिल करने की औपचारिकता को रेखांकित किया गया, जो बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समूह की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
- ब्रिक्स में ईरान का प्रवेश एक रणनीतिक कदम है, जिससे ईरान और वर्तमान ब्रिक्स सदस्यों दोनों को लाभ होगा।

ईरान के लिए

- यह पश्चिमी आर्थिक प्रतिबंधों का प्रतिकार करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अधिक गहराई से एकीकृत होने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
 - यह विश्व की कुछ सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग के लिए नए मार्ग प्रशस्त करता है।
- ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) ईरान में बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिससे आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे।

ब्रिक्स के लिए

- इससे मध्य पूर्व में समूह का प्रभाव बढ़ता है, जो कि भू-राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
- ईरान के कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार, साथ ही इसकी रणनीतिक स्थिति, इसे ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार मार्गों के लिए एक मूल्यवान साझेदार बनाती है।

भारत-ईरान संबंध: ऐतिहासिक संदर्भ

- भारत और ईरान के बीच संबंध जटिल एवं बहुआयामी हैं, जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा रणनीतिक संबंधों में गहराई से निहित हैं। वे प्राचीन काल से सांस्कृतिक और सभ्यतागत आदान-प्रदान का समृद्ध इतिहास साझा करते हैं।
- भारतीय कला, वास्तुकला तथा भाषा पर फ़ारसी प्रभाव अच्छी तरह से प्रलेखित है, और दोनों देश ऐतिहासिक रूप से व्यापार मार्गों एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से जुड़े हुए हैं।
- पिछले कुछ वर्षों में, दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखने और मजबूत करने के लिए विभिन्न वैश्विक तथा क्षेत्रीय चुनौतियों का सामना किया है।

राजनीतिक संबंध

- 1950:** भारत-ईरान मैत्री संधि पर हस्ताक्षर।
- 2001:** प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ईरान यात्रा और तेहरान घोषणापत्र पर हस्ताक्षर।
- 2003:** राष्ट्रपति सैय्यद मोहम्मद खातमी की भारत यात्रा और नई दिल्ली घोषणापत्र पर हस्ताक्षर।
- 2016:** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा, जिसके परिणामस्वरूप भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच व्यापार, परिवहन तथा पारगमन पर त्रिपक्षीय समझौते सहित 12 समझौता ज्ञापनों/समझौतों पर हस्ताक्षर हुए।

- **2018:** राष्ट्रपति हसन रूहानी की भारत यात्रा, जिसके दौरान स्वास्थ्य, चिकित्सा और चाबहार बंदरगाह के अंतरिम संचालन जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 13 समझौता ज्ञापनों/समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

आर्थिक और व्यापारिक संबंध

- वित्तीय वर्ष 2022-23 में द्विपक्षीय व्यापार 2.33 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें ईरान को भारत का निर्यात 1.66 बिलियन डॉलर और ईरान से आयात कुल 672.12 मिलियन डॉलर था।

सामरिक एवं सुरक्षा सहयोग

- भारत और ईरान ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई द्विपक्षीय परामर्श तंत्र स्थापित किए हैं, जिनमें शामिल हैं:
 - संयुक्त समिति बैठकें (JCM)
 - विदेश कार्यालय परामर्श (FOC)
 - राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के स्तर पर सुरक्षा परामर्श
 - संयुक्त कांसुलर समिति बैठकें (JCCM)
- ये तंत्र रणनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर नियमित बातचीत की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता तथा आपसी हितों में योगदान मिलता है।

भारत-ईरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना

- भारत एवं ईरान दोनों ने अपने देशों के बीच मजबूत ऐतिहासिक तथा सभ्यतागत संबंधों को स्वीकार किया और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया।
- 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान उन्होंने ऊर्जा, व्यापार और कनेक्टिविटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की, जिसमें चाबहार बंदरगाह तथा अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) पर विशेष ध्यान दिया गया।

ऊर्जा सहयोग

- ऊर्जा सहयोग भारत-ईरान संबंधों की आधारशिला बना हुआ है। 2019 से पहले, ईरान भारत की कच्चे तेल की आवश्यकताओं का लगभग 12% आपूर्ति करता था। आर्थिक प्रतिबंधों और क्षेत्रीय संघर्षों के बावजूद, ईरान के कच्चे तेल के उत्पादन तथा निर्यात ने लचीलापन दिखाया है।
 - मई 2024 में ईरान का कच्चे तेल का उत्पादन बढ़कर 3.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो गया, जो भारत की ऊर्जा मांगों को पूरा करने की उसकी क्षमता को दर्शाता है।
- ऊर्जा संबंधों को नवीनीकृत करने की संभावना चर्चा का एक महत्वपूर्ण विषय था, तथा दोनों नेताओं ने इस सहयोग को बढ़ाने के तरीकों की खोज की।

रणनीतिक कनेक्टिविटी परियोजनाएं

- मध्य एशिया और उससे आगे के देशों के साथ भारत के व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण जटिल चाबहार बंदरगाह चर्चा का केंद्र बिंदु रहा।
- यह बंदरगाह भारत को होर्मुज जलडमरूमध्य को पार करते हुए एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है और क्षेत्रीय संघर्षों के दौरान भी निर्बाध व्यापार सुनिश्चित करता है।
- मई 2024 में, भारत और ईरान ने बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्ष के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जो इसके रणनीतिक महत्व को रेखांकित करता है।
- इसके अतिरिक्त, चाबहार और ज़ाहेदान के बीच 700 किलोमीटर रेलवे लिंक के विकास और अफ़गानिस्तान के साथ आगे की कनेक्टिविटी पर भी प्रकाश डाला गया।

- इन परियोजनाओं से व्यापार और मानवीय सहायता मार्गों को बढ़ावा मिलने, क्षेत्रीय स्थिरता एवं आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने की उम्मीद है।

क्षेत्रीय स्थिरता और शांति

- गाजा में चल रहे संघर्ष को देखते हुए ईरान ने संकट को कम करने में भारत का सहयोग मांगा। भारत, जो अपने संतुलित कूटनीतिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है, युद्धविराम और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता रहा है।
- ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ने दोनों देशों को क्षेत्रीय स्थिरता और शांति को बढ़ावा देने में अपनी भूमिकाओं पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान किया।

भारत-ईरान संबंधों में चिंताएं और चुनौतियां

- **प्रतिबंध और आर्थिक बाधाएँ:** ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के फिर से लागू होने से भारत-ईरान व्यापार संबंधों पर अत्यंत प्रभाव पड़ा है।
 - इन प्रतिबंधों ने भारत की ईरानी तेल आयात करने की क्षमता को सीमित कर दिया है, जो उनके द्विपक्षीय व्यापार का एक प्रमुख घटक था।
 - आर्थिक बाधाओं ने फार्मास्यूटिकल्स और चाबहार पोर्ट जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं सहित अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित किया है।
- **भू-राजनीतिक तनाव:** पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक परिदृश्य, विशेष रूप से ईरान और सऊदी अरब तथा इज़राइल जैसी अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के बीच तनाव, भारत के कूटनीतिक संतुलन को जटिल बनाता है।
 - इन देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी में हितों के टकराव से बचने के लिए सावधानीपूर्वक संचालन की आवश्यकता है।
- **सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:** आतंकवाद और क्षेत्रीय अस्थिरता सहित सुरक्षा संबंधी मुद्दे महत्वपूर्ण चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं।
 - अफ़गानिस्तान की स्थिति, जहाँ भारत और ईरान दोनों के निहित स्वार्थ हैं, जटिलता की एक परत जोड़ती है।
 - आतंकवाद-रोधी प्रयासों में सहयोग महत्वपूर्ण है, लेकिन अलग-अलग क्षेत्रीय प्राथमिकताओं और गठबंधनों के कारण चुनौतीपूर्ण है।
- **कनेक्टिविटी परियोजनाएँ:** चाबहार पोर्ट और INSTC जैसी परियोजनाएँ कनेक्टिविटी और व्यापार को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन्हें रसद, वित्तीय और राजनीतिक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
 - इन परियोजनाओं का समय पर पूरा होना और परिचालन दक्षता सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है।
- **ऊर्जा निर्भरता:** ईरान पर भारत की ऊर्जा निर्भरता दोधारी तलवार रही है। जबकि ईरान के कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्षेत्र में अस्थिरता और प्रतिबंधों ने इस निर्भरता को जोखिम भरा बना दिया है।
 - ईरान के साथ रणनीतिक संबंध बनाए रखते हुए ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना एक नाजुक संतुलन है।

निष्कर्ष और आगे की राह

- भारत-ईरान संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं के बीच स्थायी संबंधों का प्रमाण है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ने निस्संदेह भारत-ईरान संबंधों को महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया है।

- रणनीतिक परियोजनाओं, ऊर्जा सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करके, दोनों देशों ने एक मजबूत तथा अधिक लचीली साझेदारी के लिए आधार तैयार किया है।
- चूंकि भारत वैश्विक कूटनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखता है, इसलिए ईरान के साथ उसका संबंध पश्चिम एशिया के भू-राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण होगा।

Source: TH



दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न. हाल ही में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ने भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को किस सीमा तक मजबूत किया है? क्षेत्रीय भू-राजनीति और वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर इस मजबूत साझेदारी के संभावित प्रभावों पर चर्चा करें।

